प्रसार भारती
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
18.06.2025 / प्रादेशिक समाचार / 19:45बजे

"आज के मुख्य समाचार"

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 की बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल के लिए दो हजार 6 करोड़ रुपये से अधिक की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निमार्ण योजना को दी मंजूरी।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने टीबी की नियमित निगरानी, जनभागीदारी व जागरूकता पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला ज़िला के ठियोग में नए बस अड्डे व शिलारू में फल व सब्जी विपणन परिसर का किया लोकार्पण।
- शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा—शून्य से 25 फीसदी परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों को नोटिस जारी—अध्यापकों की जवाबदेही होगी तय।

केन्द्रीय सहायता

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2 हजार 6 करोड़ 40 लाख रुपये के कुल परिव्यय के साथ "रिकवरी और पुनर्निर्माण योजना" को मंजूरी दी है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि एनडीआरएफ के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से राज्य को वित्तीय सहायता के प्रस्ताव पर विचार किया। इस धनराशि से राज्य को 2023 मानसून के दौरान बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन के कारण होने वाली क्षति व विनाश के कारण रिकवरी व पुनर्निर्माण गतिविधियों में मदद मिलेगी। इसमें 15 सौ 4 करोड़ 80 लाख रुपये राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केन्द्र का हिस्सा होगा। इससे पूर्व, गृह मंत्रालय ने इस आपदा से प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिय, 12 दिसम्बर 2023 को ही एनडीआरएफ से 6 सौ 33 करोड़ 73 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी थी।

केन्द्रीय सहायता–2

इस बीच भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने इस धनराशि के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि देव भूमि हिमाचल में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में इस आर्थिक सहायता से महत्वपूर्ण संबल मिलेगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर और पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने भी हिमाचल प्रदेश को ये धनराशि प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।

राज्यपाल

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने टीबी उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए राज्य व ज़िला स्तर पर टीबी की नियमित निगरानी, जनभागीदारी और जागरूकता पर बल दिया है। राज्यपाल आज राजभवन शिमला में टीबी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में सौ दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत हिमाचल प्रदेश द्वारा किए गए कार्यों के मूल्यांकन सहित केंद्र सरकार द्वारा देशभर में संचालित टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की

प्रगति पर चर्चा की गई। शिव प्रताप शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में हो रहे प्रयासों की सराहना की और विभिन्न ज़िलों में टीबी उन्मूलन के लिए किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी की।

<u>मुख्यमंत्री</u>

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला जिला के ठियोग में 14 करोड़ 84 लाख रुपये से निर्मित नए बस अड्डे और शिलारू में 23 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित एपीएमसी फल व सब्जी विपणन परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर ठियोग में एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे में यात्रियों व एचआरटीसी के स्टाफ को सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी और बस पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों व बागवानों के हित में फैसले ले रही है और किसानों को उनके घर–द्वार के समीप बेहतर विपणन सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सेब बागवानों को लाभ प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले साल में ही यूनिवर्सल कार्टन के उपयोग को लागू किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से विदेशों से आयात होने वाले सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

<u>मुख्यमंत्री –2</u>

इस दौरान मुख्यमंत्री ने ठियोग में एचआरटीसी का सब डिपो और वर्कशॉप खोलने की घोषणा भी की। इस अवसर पर उप–मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कृषि मंत्री चंद्र कुमार और विधायक कुलदीप सिंह राठौर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे।

<u>रोहित ठाकुर</u>

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि वार्षिक परीक्षा परिणामों में निराशाजनक प्रदर्शन वाले स्कूलों में अध्यापकों की जवाबदेही तय की गई है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि ऐसे स्कूल जहां परीक्षा परिणाम शून्य से 25 फीसदी के बीच रहे हैं उन स्कूलों को नोटिस जारी करने के साथ ही अध्यापकों की इंक्रीमेंट भी उस वर्ष के लिए रोक दी गई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि आने वाले समय में स्कूलों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।

थे जहां पर रिजल्ट आपके निराशा जनक रहे हैं, विशीष कर आपका 0% से 25% के बीच सबको नोटिस भी जारी हुए और साथ ही उसमें इंक्रीमेंट भी उस वर्ष की रोक दी गई ह□ लेकिन टीचर्स की जवाब देई हो, उनके म□ समझता हूँ रिस्पॉसिबिल्टी फिक्स की जाए साथ ही साथ जो हेड ऑफ दी institution होंगे उनकी भी हम responsibility फिक्स करना चाह रहे हैं और कई ऐसे भी मामले हमे देखने को आए चलो जहां तो स्टाफ का अभाव ह□ वो तो एक मानी भी जा सकती ह□ बात लेकिन जहां पर आपका 100% स्टाफ था और result बहुत ही निराशाजनक रहे इस बात को justify नहीं किया जा सका और इस

बात को लेकर सरकार बिल्कुल सीरियस है हमारी quality education वर्तमान सरकार की पहली प्राथमिकता है।

शांडिल

स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि प्रदेश सरकार सैनिकों, पूर्व सैनिकों व उनके परिवारों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शिमला में आज सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने ये बात कही। धनीराम शांडिल ने कहा कि सेनाओं में हिमाचल के वीर सपूतों का प्रतिनिधत्व जनसंख्या के अनुपात में सर्वाधिक रहा है और प्रदेश के बहादुर सैनिकों ने देश की रक्षा व अखंडता के लिए सदैव उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान की हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों में निर्माणाधीन सैनिक सदन, प्रशिक्षण अकादमी, नुरपूर और फतेहपुर में बनने वाले शहीद स्मारक व सैनिक कल्याण से जुड़े अन्य संस्थानों का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। शांडिल ने कहा कि प्रदेश सरकार जल्द ही राज्य सैनिक बोर्ड और पुनर्वास व पुनर्निमार्ण कोष प्रबंधन समिति का गठन करेगी।

जगत सिंह नेगी

राजस्व व जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी ने अधिकारियों को किन्नौर ज़िले के कल्पा व निचार में चलाए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज रिकांगपिओ में लोक निर्माण विभाग कल्पा व निचार मंडल के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। जगत सिंह नेगी ने ज़िले में सड़क दुर्घटना के ब्लैक स्पॉटस में क्रैश बैरियर लगाने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने मॉनसून व सेब सीजन के दृष्टिगत सम्पर्क सड़क मार्गों को दरूस्त रखने के निर्देश भी दिए।

इससे पहले राजस्व मंत्री ने किन्नौर–कैलाश यात्रा के सफल आयोजन को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता भी की। इस दौरान उन्होंने संबधित विभाग के अधिकारियों को यात्रा के लिए सभी आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए।

नरेश चौहान

मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार पूरी पारदर्शिता व ईमानदारी से कार्य कर रही है। शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुलिस भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ा रही है जिसमें भ्रष्टाचार की कोई संभावना नहीं है। नरेश चौहान ने कहा कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर राज्य सरकार पर बिना तथ्यों के आरोप लगा रहे हैं।

मुख्य सचिव

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। शिमला में आज एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने नागरिक सुरक्षा के तहत स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित करने, बांध प्रबंधन प्राधिकरणों के साथ

व्यापक समन्वय स्थापित करने और अवरूद्ध सड़कों, पेयजल योजनाओं की बहाली के लिए व्यापक स्तर पर प्रबंध करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिला उपायुक्तों को अपने–अपने स्तर पर कार्य योजना बनाने और कार्यान्वित कार्य करने को कहा। बैठक में वर्चुअल माध्यम से सभी जिलों के उपायुक्तों व अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने मानसून को लेकर की गई तैयारियों की विस्तृत जानकारी दी।

योग दिवस

21 जून को आयोजित किए जाने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को लेकर प्रदेशभर में तैयारियां जोरों पर है। इसी कड़ी में सोलन जिला आयुष विभाग ने एक जागरूकता रैली के माध्यम से लोगों को योग के बारे में जागरूक किया। दूसरी ओर योग दिवस पर मंडी का जिला स्तरीय कार्यक्रम सेरी मंच पर होगा। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने आयुष विभाग को उपमंडल अधिकारियों के साथ समन्वय बनाकर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्य समाचार एक बार फिर

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 की बाढ़, भूस्खलन व बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल के लिए दो हजार 6 करोड़ रुपये से अधिक की पुनर्प्राप्ति व पुनर्निमार्ण योजना को दी मंजूरी।
- राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने टीबी की नियमित निगरानी, जनभागीदारी व जागरूकता पर दिया बल।
- मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला ज़िला के ठियोग में नए बस अड्डे व शिलारू में फल व सब्जी विपणन परिसर का किया लोकार्पण।
- शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा–शून्य से 25 फीसदी परीक्षा परिणाम वाले स्कूलों को नोटिस जारी–अध्यापकों की जवाबदेही होगी तय।

———————————————